दूरी वाले/दुर्गम क्षेत्रों के कारण असंचालनीय हो ;

(ii) किसी ग्रामीण शाखा के कारोबार में वृद्धि, जिसके अतिरिक्त बैंक शाखा खोलना न्यायसंगत हो और यह शाखा अर्थक्षम हो सकती है ।

(iii) पर्वतीय/पिछड़े और दूरस्थ क्षेत्रों के मामले में, इन क्षेत्रों को विधिवत वेटेज दिया जाना होता है ।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को स्वयं ही ग्रामीण क्षेत्रों में शाखायें खोलने की स्वतंत्रता दी गयी है बशर्ते कि उन्होंने अपेक्षित पूंजी पर्याप्तता संबंधी मानदंडों को पूरा कर लिया हो तथा विवेकपूर्ण लेखा मानकों का अनुपालन करते हों ।

उत्तर प्रदेश द्वारा केन्द्रीय ऋण का उपयोग

2798. **श्री ईश दत्त यादव :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केंद्रीय सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश को प्रतिवर्ष कितनी ऋण सहायता प्रदान की गई ;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान उक्त सहायता से शुरू/कार्यान्वित किए गए कार्यों/कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) 1991–92 के वर्ष के दौरान राज्य में किन-किन क्षेत्रों में कार्यों/कार्यक्रमों को शुरू/कार्यान्वित किया जा रहा है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शान्ताराम पोटदुखे) : (क) उत्तर प्रदेश सरकार को पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष सामान्य केंद्रीय सहायता, बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं तथा पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रमों के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता के अंतर्गत दी गई ऋण सहायता की राशि नीचे दी गई है :—

वर्ष	(करोड़ रुपए में)
1989–90	725.84
1990–91	902.58
1991–92	1340.43

(ख) और (ग) राज्यों को उनके वार्षिक योजना परिव्ययों तथा अन्य क्षेत्र कार्यक्रमों की वित्त व्यवस्था के लिए सहायता एक मुश्त ऋणों तथा एकमुश्त अनुदानों के रूप में दी जाती है और वे किसी खास कार्य/कार्यक्रम से जुड़े हुए नहीं होते हैं ।

Complaint by officers of State Bank of Saurashtra

2799. SHRI P. UPENDRA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Officers of the State Bank of Saurashtra have complained against discriminatory attitude of the State Bank of India towards their bank; and

(b) if so, what action Government have taken to remedy the situation?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI DALBIR SINGH): (a) and (b) The information is being collected and to the extent available, will be laid on the Table of the House.

US bank advnces to Indian for purchase of cars made in USA

2800. SHRI CHATURANAN MISHRA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a US Bank advanced money to Indian citizens for purchasing fancy cars made in USA;

(b) if so, whether it is also a fact that musclemen were engaged and cars were

forcibly seized by the Bank from some creditors who did not pay the instalments; and

(c) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI DALBIR SINGH): (a) and (b) Reserve Bank of India have reported that in the absence of specific complaints they had no occasion to investigate this matter.

(c) Does not arise.

बैंकिंग क्षेत्र में सुधार

2801. **श्री विनोद शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार वर्तमान बैंकिंग प्रणाली में सुधार लाने के लिए एक नया आयोग गठित करने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि नवम्बर, 1991 में श्री नरसिम्हम की अध्यक्षता में गठित समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ग) यदि हां, तो उक्त प्रतिवेदन के आधार पर सरकार द्वारा बैंकिंग प्रणाली में अब तक क्या सुधार किए गए हैं ;

(घ) सरकार द्वारा किन-किन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है परंतु उन्हें अब तक कार्यान्वित नहीं किया गया है ; और

(ङ) बैंकिंग प्रणाली के किन-किन पहलुओं को सुधारने के लिए उन्हें प्रस्तावित नए आयोग को सौंपे जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (घ) वित्तीय प्रणाली अध्यक्ष एम नरसिंहम पर समिति का गठन अगस्त 1991 में किया गया था और उसकी रिपोर्ट सरकार को नवंबर 1991 में प्राप्त हुई थी । समिति की सिफारिशों के अनुक्रम में किए गए सुधारात्मक उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं: एस.एल.आर और सी.आर.आर. में कमी, ब्याज दर संरचना का सरलीकरण, पूंजी पर्याप्तता के संबंध में मानकों का निर्धारण, आय की पहचान और प्रावधान संबंधी अपेक्षायें, अधिक सुस्पष्टता के लिए तुलन पत्र और लाभ तथा हानि फार्मेटों का संशोधन, शाखा लाइसेंसिंग के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के मार्ग-निर्देशों में संशोधन, पूंजी बाजार को उदार करने के उपाय, एस.ई.बी.आई को सांविधिक शक्तियां प्रदान करना, विभिन्न म्यूचुअल फण्डों से कर में रियायतों के मामले में एक समान व्यवहार करना आदि । समिति की अन्य सिफारिशें विचाराधीन हैं ।

(ङ) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न पैदा ही नहीं होता ।

Recovery of agricultural loans

2802. DR. YELAMANCHILI SIVAJI: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the State Governments are being asked to apply Revenue Recovery Act for recovery of Agricultural loans advanced by Nationalised Banks; and

(b) if so, what is the response of various State Governments thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI DALBIR SINGH): (a) and (b) An Expert Group on State Enactment having a bearing on commercial banks' lending to agriculture (Talwar Committee) had recommended enactment on legislation by various State Governments and Union Territories on the lines of 'Model Bill' evolved by them for the purpose. In pursuance of the above recommendation, State Governments were advised to enact legislation for speedy recovery of agricultural advances of commercial banks. The following 16 States have already enacted the legislation on the subject: (1) Assam, (2) Bihar, (3) Gujarat (4) Haryana, (5) Himachal Pradesh, (6) Karnataka, (7) Madhya Pradesh, (8) Maharash-